



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 191]

मई दिल्ली, बुधवार, मार्च 20, 1996/फाल्गुन 30, 1917

No. 191]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 20, 1996/PHALGUNA 30, 1917

निधि, न्याय और गम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मार्च, 1996

का. आ. 227(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

आदेश

श्री शिव प्रसाद चनपुरिया, समस्त सदस्य (राज्य सभा) द्वारा तारीख 7-3-1995 को यह अभिकथन करते हुए एक याचिका दायर की गई है कि श्री अर्जुन सिंह, आमीन समस्त सदस्य (लोक सभा), ने वर्ष 1980 से धन, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों के अनुपात में नहीं है, संग्रह किए जाने के कारण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 88 और प्रांताचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ड) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 के अधीन निरहेता उपगत की है ;

और भारत के राष्ट्रपति ने उक्त याचिका के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (2) के अधीन निर्वाचन आयोग की राय मांगी है ;

और निर्वाचन आयोग की यह राय है (उपान्वध देखें) कि याची द्वारा संविधान के अनुच्छेद 103 के अधीन श्री अर्जुन सिंह की अभिकथित निरहेता के संबंध में राष्ट्रपति की अधिकारिता का अवलम्ब नहीं लिया जा सकता ;

अतः अब मैं, शंकर दयाल शर्मा, भारत का राष्ट्रपति, श्री शिव प्रसाद चनपुरिया की पूर्वोक्त याचिका खारिज करता हूँ।

मार्च, 14, 1996

भारत का राष्ट्रपति

उपाबंध

भारत निर्वाचन आयोग

भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष 1995 का निर्देश मामला सं. 1 (भारत के राष्ट्रपति का भारत के संविधान के अनुच्छेद 104 के अधीन निर्देश)

निर्देश : लोक सभा के आसीन सदस्य श्री अर्जुन सिंह की अभिकल्पित निरर्हता।

राय

1.1 यह भारत के राष्ट्रपति से तारीख 8-9-1995 का निर्देश है, जिसमें इस प्रश्न पर कि क्या श्री अर्जुन सिंह, आसीन संसद सदस्य, भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 के अधीन निरर्हता से ग्रस्त हो गए हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन भारत निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई।

1.2 उपरोक्त निर्देश श्री शिव प्रसाद चनपुरिया, संसद सदस्य (राज्यसभा) जो ग्राम बहाराजी, तहसील कृष्णम, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश के निवासी हैं, द्वारा श्री अर्जुन सिंह, संसद सदस्य की निरर्हता की मांग करने वाली भारत के राष्ट्रपति के समक्ष तारीख 7-3-1995 की याचिका पर उद्भूत हुआ।

2. श्री अर्जुन सिंह, जून, 1991 में हुए साधारण निर्वाचन में 8-संख्यक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचित लोक सभा के सदस्य हैं। याची ने, अपने तारीख 7-3-1995 के आस्थापित में, यह प्रकट किया है कि श्री अर्जुन सिंह को, वर्ष 1960 से, जब उन्होंने मध्य प्रदेश विधान सभा के पद पर पहली बार अपनी आस्तियों के बारे में प्रकट किया था धन, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों के अनुपात में नहीं है, संग्रह करने के कारण सशस्त्र का सदस्य बने रहने से निरर्हत कर दिया जाए। याची ने श्री कलाण जोशी द्वारा फाइल की गई 1987 की प्रकीर्ण याचिका सं. 3909 में, जिसका विनिश्चय 28-7-1989 को किया गया था, पारित मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय का संदर्भ दिया है, जिसमें ऐसी रिपोर्ट मिली है कि माननीय न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि "हम याची के सभी प्रकथनों को सही स्वीकार नहीं कर रहे हैं किन्तु श्री अर्जुन सिंह को उस परिस्थिति को, जो 28 वर्ष पूर्व विधान सभा में उनके पहली बार कथन के अनुसार दूषित और दूषित हो गया है, दूर करने के लिए संदेहों का लोकहित में निराकरण करना है।" इस आधार पर याची ने प्रार्थना की है कि श्री अर्जुन सिंह को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के साथ पठित और अप्रत्याचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(ड) के साथ भी पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 के अधीन निरर्हत कर दिया जाए।

3. अब, मूल प्रश्न जो उत्पन्न होता है यह है कि आयोग को इन मुद्दों पर, जो उसे निविष्ट किया गया है अपनी राय देने की अधिकारिता है या नहीं। यह सुस्थापित विधि है कि निर्वाचित आयोग की संसद के किसी सदन के किसी आसीन सदस्य की निरर्हता के प्रश्न पर जांच करने की अधिकारिता केवल उस निरर्हता, जिसके लिए सदस्य उस सदन में अपने

निर्वाचन के पश्चात् ग्रस्त हुआ है, के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 102 के अधीन उद्भूत होता है। किसी सदस्य की पूर्व निर्वाचित निरर्हता से संबंधित कोई प्रश्न, अर्थात्, ऐसी निरर्हता, जिससे कोई व्यक्ति अपने निर्वाचन के समय या उससे पूर्व ग्रस्त था, केवल निर्वाचन याचिका की विषय वस्तु है। वर्तमान मामले में, याची ने श्री अर्जुन सिंह, द्वारा 1960 की प्रार्थना से, जब वे मध्य प्रदेश विधान सभा के सदस्य के रूप में पहली बार आए, धन का संग्रह करने का अभिकथन किया है। श्री अर्जुन सिंह का, जो 1991 में निर्वाचित हुए, लोक सभा का सदस्य होने के कारण, अधिकारिता यदि कोई है, जून, 1991 में लोक सभा के सदस्य के रूप में श्री अर्जुन सिंह के निर्वाचन की तारीख के पश्चात् निरर्हता को आकृष्ट करने वाले किसी कार्य के विनिश्चित अभिकथन के मामले में ही उत्पन्न होगी। याचिका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1957 की धारा 8 और अप्रत्याचार निवारण अधिनियम, 1988 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 के साथ पठित अनुच्छेद 103 के अधीन है।

4. भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 के अनुसार "(1) कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिये और सदस्य होने के लिये निरर्हत होगा —

- (क) यदि वह भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन, ऐसे पद को छोड़कर, जिसको धारण करने वाले का निरर्हत न होना संसद ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई लाभ का पद धारण करता है ;
- (ख) यदि वह विधित्त है और मध्यम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है;
- (ग) यदि वह अनुसूचित विधायक है;
- (घ) यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है ;
- (ङ) यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निर्वाचित कर दिया जाता है।

स्पष्टीकरण—इस खंड के पर्योजनाओं के लिये, कोई व्यक्ति केवल इस कारण भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का या ऐसे राज्य का मंत्री है।

(2) कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य होने के लिये निर्वाचित होगा यदि वह दसवीं अनुसूची के अधीन इस प्रकार निर्वाचित हो जाता है।

5. याची का मामला संविधान के अनुच्छेद 102 (1)(क), (ख), (ग), (घ) या (ङ) या अनुच्छेद 102(2) के अधीन नहीं आता है। जहाँ तक इस प्रश्न का कि श्री अर्जुन सिंह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन निर्वाचित हुए हैं या नहीं, संबंध है, भाग 2 के अध्याय 3 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 7 से धारा 10(क) के प्रति निर्देश किया जाता है। यह स्पष्ट है कि श्री अर्जुन सिंह का मामला इन धाराओं में से किसी के अधीन नहीं है। यानी कि इस प्रतिनिधित्व के संबंध में कि श्री अर्जुन सिंह को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 (क) के अधीन निर्वाचित किया जाये, यह धारा बहुत ही विनिर्दिष्ट और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 99 के अधीन आदेश द्वारा भ्रष्टाचार के दोषी पाये गये व्यक्तिगो के मामलों से ही संबंधित है।

6 जहाँ तक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(ङ) के अधीन निरर्हता के संबंध में याची के प्रतिनिधित्व का संबंध है, लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के अधीन जहाँ कई अधिनिर्देशों के प्रति निर्देश किया गया है, इस अधिनियम का कोई विनिर्दिष्ट उल्लेख नहीं है। तथापि, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(3) के अन्तर्गत "कोई व्यक्ति जो उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी अपराध से भिन्न किसी अपराध के लिये सिद्धांत डहराया गया है और दो वर्ष से अन्यून के कारावास से दंडादिष्ट किया गया है, ऐसी दोषविद्धि की तारीख से निर्वाचित होगा और उसे छोड़े जाने से छह वर्ष की अनिश्चित कारावधि के लिये निर्वाचित बना रहेगा। याची का मामला यह नहीं है कि श्री अर्जुन सिंह का भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन सिद्धांत डहराया गया है और दो वर्ष से अन्यून के लिये कारावास से दंडादिष्ट किया गया है। इसके अनिश्चित ऐसी दोषविद्धि, यदि की जाती है, संबंधित व्यक्ति को स्वतः निर्वाचित कर देगी और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के अधीन राष्ट्रपति से निर्देश की विषयवस्तु नहीं है।

7. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, निर्वाचन आयोग की यह राय है कि याची द्वारा संविधान के अनुच्छेद 102 के अधीन श्री अर्जुन सिंह की अभिकथित निर्वाचन के संबंध में राष्ट्रपति को अधिकारिता का अवलंब नहीं लिया जा सकता। निर्वाचन आयोग की भी अभिकथित निर्वाचन के उपरोक्त प्रश्न की जांच करने की अधिकारिता नहीं है।

8. भारत के राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश को उपरोक्त आशय को राय सहित लाटाया जाता है।

(डा. एम. एन. गिल)

(टी. एन. शेपन)

(जी. वी. जी. कृष्णामूर्ति)

निर्वाचन आयोग

मुख्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन आयोग और अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली,

तारीख 12 जनवरी, 1996

[फा. सं. 7(3) 96-मि.-II]

पी. एल. शंकरदायल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th March, 1996

S.O. 227(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

ORDER

Whereas, a petition, dated 7-3-1995 has been filed by Shri Sheo Prasad Chanpuria, Member of Parliament (Rajya Sabha) alleging that Shri Arjun Singh, a sitting Member of Parliament (Lok Sabha) has incurred disqualification under article 120 of the Constitution of India read with section 8A of Representation of the People Act, 1951 and clause (c) of sub-section (1) of section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 for having amassed wealth disproportionate to his known sources of income since 1960;

And whereas, the President of India has sought the opinion of the Election Commission under clause (2) of article 103 of the Constitution with reference to the said petition;

And whereas, the Election Commission is of the opinion (vide Annex) that the jurisdiction of the President under article 103 of the Constitution cannot be invoked by the petitioner in relation to the alleged disqualification of Shri Arjun Singh;

Now, therefore, I, Shanker Dayal Sharma, President of India, do hereby dismiss the aforesaid petition of Shri Sheo Prasad Chanpuria.

March 14, 1996

PRESIDENT OF INDIA

ANNEX

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Before the Election Commission of India

Reference Case No. 1 of 1995

(Reference from the President of India under Article 103 of the Constitution of India)

In Re : Alleged disqualification of Shri Arjun Singh
a sitting member of Lok Sabha.

OPINION

1.1 This is a reference dated 8-9-1995 from the President of India seeking the opinion of the Election Commission of India under Article 103(2) of the Constitution of India on the question whether Shri Arjun Singh, a sitting member of Parliament, has become subject to disqualification under Article 102 of the Constitution of India.

1.2 The above reference arose on a petition dated 7-3-1995 before the President of India, by one Shri Sheo Prasad Chanpuria, Member of Parliament (Rajya Sabha), and resident of Village Baharaji, Tahsil Kundam, District Jabalpur, Madhya Pradesh seeking disqualification of Shri Arjun Singh, Member of Parliament.

2. Shri Arjun Singh is member of the Lok Sabha elected from 8-Satna Parliamentary Constituency in the general election held in June, 1991. The petitioner, in his representation, dated 7-3-1995 has averred that Shri Arjun Singh may be disqualified from being a member of Parliament for having amassed wealth disproportionate to his known sources of income, since 1960, when he had first made disclosures about his assets on the floor of the MP Legislative Assembly. The petitioner has referred to a judgement of the High Court of Madhya Pradesh passed in Misc. Petition No. 3909 of 1987 filed by Shri Kailash Joshi decided on 28-7-1989 wherein the Hon'ble Court is reported to have observed that "we are not accepting all the averments of the petitioner to be true but Shri Arjun Singh has to clear the clouds in public interest in order to cleanse the atmosphere which is vitiated and polluted according to his very first statement in the Vidhan Sabha 28 years back. "On this ground the petitioner has prayed that Shri Arjun Singh may be disqualified under Article 102 of the Constitution of India read with Section 8A of Representation of People Act, 1951 and also read with Section 13(1) (e) of the Prevention of Corruption Act, 1988.

3. Now, the basic question that arises is whether the Commission has the jurisdiction to give its opinion on the issue referred to it or not. It is well-settled law that the jurisdiction of the Election Commission to enquire into the question of disqualification of a sitting member of either House of Parliament arises under Article 102 of the Constitution only in relation to that qualification to which the member has become subject after his election to that House. Any question relating to pre-election disqualification of a member, that is to say a disqualification from which a person was suffering at the time of or prior to his election, is a subject-matter of an election petition only. In the instant case, the petitioner has alleged

amassing of wealth by Shri Arjun Singh since the period 1960 when he made his debut as a member of the Madhya Pradesh Legislative Assembly. Shri Arjun Singh being a member of the Lok Sabha elected in 1991, the jurisdiction, if any, will arise only in case of a specific allegation of any act attracting disqualification after the date of election of Shri Arjun Singh as member of the Lok Sabha in June, 1991. The petition is under Article 103 read with Article 102 of the Constitution of India read with Section 8A of the Representation of the People Act, 1951 and read with Section 13(1) (e) of the Prevention of Corruption Act 1988.

4. According to Article 102 of the Constitution of India "(1) a person shall be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament —

- (a) if he holds any office of profit under the Govt. of India or the Govt. of any State, other than an office declared by Parliament by law not to disqualify its holder;
- (b) if he is of unsound mind and stands so declared by a competent court;
- (c) if he is an undischarged insolvent;
- (d) if he is not a citizen of India, or has voluntarily acquired the citizenship of a foreign State;
- (e) if he is disqualified by or under any Law made by Parliament.

Explanation.—For the purposes of this clause a person shall not be deemed to hold an office of profit under the Government of India or the Government of any State by reason only that he is a Minister either for the Union or for such State.

(2) A person shall be disqualified for being a member of either House of Parliament if he is so disqualified under the Tenth Schedule."

5. The case of the petitioner is not covered under Article 102 (1), (a), (b), (c) (d) or (e) or Article 102(2) of the Constitution. In so far as the question whether Shri Arjun Singh is disqualified by or under any law made by Parliament is concerned, reference has to be made to Section 7 to Section 10A of the R. P. Act, 1951, in Chapter III of Part II. It is clear that the case of Shri Arjun Singh is not under any of these sections. As regards the contention of the petitioner that Shri Arjun Singh may be disqualified under Section 8A of the R. P. Act, 1951, this section is very specific and relates only to cases of persons found guilty of a corrupt practice by an Order under Section 99 of the R. P. Act, 1951.

6. As regards the contention of the petitioner regarding the disqualification under Section 13(1)(e) of the Prevention of Corruption Act, 1988, there is no specific mention of this Act under Section 8 of the R. P. Act, 1951 where reference is made to a

number of enactments. However, under Section 8(3) of the R. P. Act, 1951, "A person convicted of any offence and sentenced to imprisonment for not less than two years (other than any offence referred to any sub-section(1) or sub-section (2) shall be disqualified from the date of such conviction and shall continue to be disqualified for a further period of six years since his release. It is not the case of the petitioner that Shri Arjun Singh has been convicted and sentenced to imprisonment for not less than two years under the Prevention of Corruption Act, 1988. Further, such a conviction if made, will automatically disqualify the person concerned and is not the subject matter of a reference from the President under Article 103 of the Constitution of India.

7. In the light of the above the Election Commission is of the opinion that the jurisdiction of the President under Article 102 of the Constitution cannot be invoked by the petitioner in relation to the alleged disqualification of Shri Arjun Singh. The

Election Commission also has no jurisdiction to enquire into the above question of alleged disqualification.

8. The reference received from the President of India is returned with the opinion to the above effect.

G. V. S. KRISHNAMURTY,
ELECTION COMMISSIONER

(DR. M. S. GILL
ELECTION COMMISSIONER

(T. N. SESHAN)
CHIEF ELECTION
COMMISSIONER &
CHAIRMAN ELECTION
COMMISSION
New Delhi

Dated : 12th January, 1996.

[F. No. 7(3)/96-Leg. II]
P. L. SAKARWAL, Jt. Secy.

